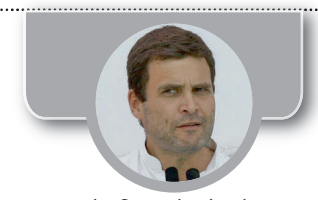

उत्तर प्रदेश के लिए हमने कहा था कि अगर हम राज्य में सरकार बनाते हैं तो हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे। यह लागत केंद्र सरकार के खजाने से वहन की जाएगी।

- राधामोहन सिंह

मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहूंगी कि हमारी सरकार भारतीय मछुआरों की सुरक्षा, हिफाजत और देखभाल को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है।

- सुषमा स्वराज

भाजपा ने मणिपुर और गोवा में धनबल का इस्तेमाल किया। उन्होंने लोगों का बहुमत चुराया।

- राहुल गांधी

## बाजीगर का नाम भाजपा

हार को जीत में बदलना कोई भाजपा नेताओं से सीखे, पांच राज्यों में से एक राज्य पंजाब में कांग्रेस को समेटकर भाजपा ने जता दिया है कि अभी भी मोदी की लहर कम नहीं हुई है। गोवा और मणिपुर में बहुमत नहीं होने के बावजूद भी वहां अपने सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार को बनाकर कांग्रेस को अचरच में डाल दिया है, भारतीय लोकतंत्र में अब तक यही बताया जाता रहा है कि जो पार्टी सबसे बड़ी होती है, सरकार बनाने का मौका उसे ही मिलता है। लेकिन अब बहुत सारी बातें बदल रही हैं तो क्या आश्चर्य कि दूसरे स्थान पर रहने वाली पार्टी को सरकार बनाने का न्यौता राज्यपाल दे रहे हैं। कांग्रेस ने राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। लेकिन यह स्थिति आज निर्मित नहीं हुई है। बरसों से केंद्र पर काबिज सरकारें प्रदेशों में अपनी पसंद का राज्यपाल नियुक्त करती हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर वह उनकी इच्छा और सुविधा मुताबिक काम करे, पहले कांग्रेस सरकारों ने यही किया, अब भाजपा यही कर रही है। दरअसल बहुमत साबित न होने पर सरकार गठन की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, इस बारे में हमारे संवैधानिक प्रावधानों की अस्पष्टता से ही राज्यपालों के मार्फत केंद्र सरकार मनमाना खेल खेल सकती है। एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है तो सरकार बनाने का दावा करने का हक किसे है, चुनाव पूर्व के गठबंधन, चुनावबाद के गठबंधन, सबसे ज्यादा सीटें हासिल करने वाली पार्टी या अधिक विधायकों के समर्थन का दावा करने वाली पार्टी, इनमें से किसे सरकार बनाने का हक है। इन सवालों पर संविधान में प्रावधान स्पष्ट नहीं हैं। गोवा और मणिपुर में अगर भाजपा बहुमत का दावा कर रही है, तो उसमें कितनी नैतिकता है, इसका परीक्षण क्यों नहीं होना चाहिए, उसने जिन विधायकों के समर्थन का दावा किया है, क्या वे चुनाव के पहले उसके साथ थे, अगर नहीं तो सरकार बनाने की बात पर साथ क्यों आए हैं, अगर इन सवालों के जवाब तलाशें जाएं तो सत्ता के लिए खरीद-फरोख्त का कड़वा सच सामने आएगा। राजनैतिक दल तो इसके उजागर होने में असुविधा महसूस करेंगे, लेकिन लोकतंत्र की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय को यह पहल करनी चाहिए थी। हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, यह संवाद शाहरुख खान के कारण बहुत चर्चित हुआ था। जब सवाल केवल जीत और हार का हो, तो सारी मर्यादाएंए नैतिकताए मूल्य ताक पर रख दिए जाते हैं और जो जीता वही सिकंदर के ध्येय को अपना लिया जाता है। फिलहाल भाजपा बाजीगर और सिकंदर दोनों नजर आ रही है। उत्तरप्रदेश और उत्तराखंड में शानदार बहुमत से वह अपनी सरकार बना रही है, लेकिन गोवा का हाथ से फिसलना उसे मंजूर नहीं था और मणिपुर की सत्ता पाने की जो उम्मीदें थी, उसे नाकाम कैसे होने दिया जाता। लिहाजा दूसरे स्थान पर रहने के बावजूद भाजपा ने सरकार बनाने का दावा पेश किया,वहां के राज्यपालों ने इसे मंजूर किया और अब दोनों ही हारे हुए प्रदेशों की सत्ता भाजपा ने राजनीतिक दांव-पेंचों से जीत ली है। सत्ता की इस दौड़ में कांग्रेस पता नहीं खरगोश बनी या कछुआ, लेकिन आज की सच्चाई यह है कि उसने सरकार बनाने का हाथ आया मौका आसानी से जाने दिया। गोवा में मनोहर पार्रिकर के मुख्यमंत्री बनने के पहले कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि यहां उसे पहले अवसर मिलना चाहिए था। अदालत से उसे दो टूक जवाब मिला कि आपने पहले दावा पेश क्यों नहीं किया। मणिपुर में तो कांग्रेस ने राज्यपाल से भेंट भी की, लेकिन वहां भी वीरेन सिंह में सफल रहे। गोवा में मनोबर परिकर ने बहुमत साबित कर लिया है, इससे साफ होता है कि भाजपा की रणनीति इस चुनाव मे कारगार साबित हुई है। पांच राज्यों में से चार पर कब्जाकर कांग्रेस की नींद उड़ा दी है। भाजपा की कांग्रेस मुक्त देश बनाने की मुहिम एक बार फिर सफल होती जा रही है, जिस प्रकार से कई राज्यों से कांग्रेस से विदाई हो गई है। केंद्र से कांग्रेस के चले जाने के बाद कई राज्यों से कांग्रेस को जाना पड़ा है, इतना ही नहीं कांग्रेस के कई नेताओं ने तो पार्टी को छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। इससे लगता है कि जनता के साथ ही नेताओं का भी कांग्रेस से मोहभंग हो चुका है। आने वाले समय में कांग्रेस कमजोर होती जाएगी। जिसका लाभ भाजपा को मिलेगा,और जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारे है, वहा से भी कांग्रेस का जाना तय माना जा रहा है।

## आपका मत

### क्यों निकलते है फतवे ?

इंडियन आइडल फेम नाहिद आफरीन के खिलाफ मुस्लिम संगठनों के 46 मौलवियों ने फतवे जारी किए है। किसी भी लड़की का मंच पर प्रस्तुति देना शरिया कानूनों के खिलाफ कहा गया है। भारत में रहनेवाला हर व्यक्ति यहा के संविधान से जुडा हुआ है। संविधान के साथ रहा रिश्ता बनाए रखना हर भारतीय का कर्तव्य है। पहली पसंद राष्ट्र ही होनी चाहीए। धर्मनिरपेक्ष कहे जाने वाले भारत में फतवे कैसे निकलते है? मुस्लिम समाज कि जागृत महिलाए फतवों का समर्थन नहीं करेगी। भारत में फतवा नहीं चलेगा। यहा सिर्फ संविधान ही चलेगा। संविधान के सहारे चलने वाले इस राष्ट्र में फतवों को आखिर क्यों सहा जाना चाहिए? फतवों कि वजह से समाज में अगर अशांति फैल जाने पर होनेवाली गड़बड़ी कि जिम्मेदारी फतवा निकालने वालों पर हि डालनी चाहिए। फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा ने विश्व महिला दिन पर महिलाओं के बारे में ट्विटर पर गंदी टिपनी कि थी उस समय फतवा निकालने वाले कहा थे? महिला किसी भी धर्म कि हो उसका सम्मान किया जाना चाहिए और उसे ठेच पहुचाने वालों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। फतवे के डर से गाना नहीं छोडूंगी यह कहनेवाले नाहिदा को हर भारतीयने साथ देना जरुरी है। यह कहकर नाहिदा ने फतवा निकालने वालों को करारा उत्तर दिया है। ऐसी बेटिया हि भारत कि असली ताकद है।

*मानसी जोशी*

### हार पर आत्ममंथन हो

हालिया चुनावी नतीजों के बाद मायावती ने अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ दिया। मायावती के बाद अब अखिलेश ने भी उन्हीं के सुर में सुर मिलाना शुरू कर दिया। इसके साथ ही कई अन्य बड़े नेताओं ने भी ईवीएम के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी। इसे हम इन नेताओं का मानसिक दिवालियापन ही कहेंगे, जो अपनी हार को पचा नहीं पा रहे। जो लोग यह बात कह रहे हैं कि उनके पास यह साबित करने का कोई भी सबूत नहीं है, तो जाहिर है कि ये जनता को गुमराह करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। जब भी मतदान शुरू होता है, उससे पहले हर पार्टी के पोलिंग एजेंट स्वयं उसे परखते हैं और उससे संबंधित सूचना अपने नेता को देते हैं, ताकि किसी भी गड़बड़ी का अंदाजा शुरुआती दौर में ही लग सके। इसी के साथ मतदान खत्म होने पर भी यही प्रक्रिया दोहराई जाती है। जब ईवीएम बूथ पर पहुंचती है, तो किसी को पता भी नहीं होता कि कौन सी सीरीज की मशीन उस मतदान केंद्र पर आई है। साथ ही ये मशीनें किसी भी प्रकार से इंटरनेट से भी नहीं जुड़ी होतीं। अतः यह बहुत मुश्किल है कि इसमें किसी भी प्रकार का हेर-फेर किया जा सके। उत्तर प्रदेश में तीन लाख से भी अधिक ईवीएम का प्रयोग किया गया, ऐसे में यह लगभग नामुमकिन सी बात है। जनता कोई बेवकूफ नहीं है। हार हुई है तो इसका ठीकरा ईवीएम पर या किसी और पर न फोड़ें। जनता ने आपके हिस्से यदि हार लिख दी है, तो इसे शालीनता से स्वीकार किया जाना चाहिए। यह कोई अंतिम चुनाव नहीं है और जनता सब देख रही है। बेहतर होगा कि ये दल या नेता ईमानदारी से अपनी कारगुजारियों का एक बार अवलोकन कर लें, जवाब खुद मिल जाएगा।

*डा. शिल्पा जैन सुराणा*

**आप अपना मत हमें इस पते पर भेज सकते हैं, हमारा ई-मेल पता है- newsloksatya01@gmail.com**

# सामुदायिक रेडियो से बह रही है बदलाव की बयार

सोनिया चोपड़ा

*राजधानी दिल्ली और गुड़गांव की चकाचौंध से दूर दिल्ली से मात्र 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हरियाणा के नूंह जिलेमें महिलाओं की सोच और उनको आत्मनिर्भर बनाने में सूचना और नई-नई जानकारियों से लैस संचार का सबसे पुराना, सुलभ साधन सामुदायिक रेडियो अल्फाज़ ए मेवात एफ फम 107.8 अहम भूमिका निभा रहाहै। बात सूचना की हो या विकास की, शिक्षा की हो या चिकित्सा की, शिकवा हो या शिकायत, सूचना के अधिकार की हो या कानून की बात, किस्से कहानियों हो या हो मेव इतिहास की बात, साफ-सफाई की हो या सरकारी योजनाओं की पात्रता की बात, रोजगार की हो या पेंशन की हर सूचना को जन-जन तक पहुंचा रहा।*

आधुनिक समाज महिला अधिकारों को लेकर काफी जागरूक है। इसका बड़ा कारण स्वयं महिलाएं हैं जो अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हुई हैं और उनकी जागरूकता को गति देनेके लिए कई देशी-विदेशी गैर सरकारी तथा स्वयंसेवी संस्थान काम कर रहे हैं। लेकिन ग्रामीण स्तर पर इस बदलाव का सबसे बड़ा वाहक बन रहा है सामुदायिक रेडियो यही कारण है कि सामुदायिक रेडियो के परिणामों से उत्साहित होकर सरकार इनकी संख्या बढ़ाने पर जोर दे रही है और सरकार दिसम्बर 2016 तक 519 सामुदायिक रेडियो को लाइसेंस प्रदान कर चुकी है और सरकार का लक्ष्य अगले वर्ष तक इनकी संख्या 2500 तक करने की है। लेकिन इसके बावजूद 31 दिसम्बर 2016 तक केवल 201 सामुदायिक रेडियो स्टेशन ही सुचारु रूप से काम कर रहे हैं।

वर्ष 2005 में सरकार ने समुदायों को शिक्षित करने और मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से सामुदायिक रेडियो की परिकल्पना को मूर्तरूप देने के लिए दिशा-निर्देश तय किये थे और वर्ष 2006 से कुछ सामाजिक एवं शैक्षणिक संस्थानों द्वारा सामुदायिक रेडियो स्थापित किये गये थे लेकिन 10 वर्ष के बाद भी अभी तक जिस गति से इनकी स्थापना एवं संचालन होना चाहिए था, वह नहीं हो पाया है। पिछले वर्ष जुलाई में लोकसभा में सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री श्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने एक लिखित जबावमें बताया था कि पिछले तीन सालों में सरकार को सामुदायिक रेडियो स्थापित करने के लिए 747 आवेदन मिले थे जिनमें से 62 को मंजूरी दी जा चुकी है और 474 आवेदन रद्द किये जा चुके हैं।

राजधानी दिल्ली और गुड़गांव की चकाचौंध से दूर दिल्ली से मात्र 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हरियाणा के नूंह जिलेमें महिलाओं की सोच और उनको आत्मनिर्भर बनाने में सूचना और नई-नई जानकारियों से लैस संचार का सबसे पुराना, सुलभ साधन सामुदायिक रेडियो अल्फाज़ ए मेवात एफ फम 107.8 अहम भूमिका निभा रहाहै। बात सूचना की हो या विकास की, शिक्षा की हो या चिकित्सा की, शिकवा हो या शिकायत, सूचना के अधिकार की हो या कानून की बात, किस्से कहानियों हो या हो मेव इतिहास की बात, साफ-सफाई की हो या सरकारी योजनाओं की पात्रता की बात, रोजगार की हो या पेंशन की हर सूचना को जन-जन तक पहुंचा रहा। नूंह जिले के घाघस गांव स्थित इसके केन्द्र से आसपास के लगभग 185 गांवों में बदलाव की बयार बह रही है और इसका साफ असर इन गांवों में साफ नजर आता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पहले लोग सरकार की योजनाओं से अनभिज्ञ रह जाते थे और अपात्र लोग मिलीभगत करके सरकारी योजनाओं का लाभ उठा जाते थे, अब ऐसा कतई नहीं है। लोग जहां अपने कर्तव्यों और अधिकारों को लेकर जागरूक हुए हैं वहीं सरकारी योजनाओं का लाभ अब केवल पात्र लोग ही ले पा रहे हैं। रेडियो कार्यक्रमों के जरिए लोगों में इतनी जागरूकता आ गई है कि यदि कोई गलत ढंग से सरकार की किसी योजना का लाभ उठा रहा हो तो यहां के लोग सूचना के अधिकार से जरिए पूरी जानकारी लेकर शिकायत करते हैं।

वर्ष 2012 में केन्द्रीय कृषि मंत्रालय एवं सहगल फाउंडेशन के सहयोग से स्थापित इस सामुदायिक रेडियो के सफर के बारे में पूजा ओ मुरादा, निदेशक, संचार बताती हैं कि मेव समुदाय के अति पिछड़े एवं अल्पसंख्यक बहुल इस क्षेत्र में साक्षरता दर की कमी के कारण यहां काम करना काफी चुनौतीपूर्ण है। यहां लड़कियों को किसी बाहरी व्यक्ति से बात करने की इजाजत नहीं है विशेष रूप से पुरुषों से, लेकिन अब परिस्थितियां बदली हैं। रेडियो से समुदाय को जोड़ने के लिए हमने रिपोर्टिंग एवं कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए स्थानीय समुदाय की लड़कियों एवं महिलाओं को प्रशिक्षित किया और उन्हें जिम्मेदारी सौंपी। इस सब का परिणाम यह हुआ कि समुदाय हमसे जुड़ता चला गया और अब हमने सफलता पूर्वक 5 साल पूरे कर लिए हैं और क्षेत्र में बदलाव साफ दिखाई देता है।

अगर हम नूंह जिले के गांवों की बात करें तो डिजिटल इंडिया के इस दौर में 10 प्रतिशत से कम घरों में टेलीविज़न हैं। ऐसे में जो महिलाएं पढ़ना-लिखना नहीं जानती वे रेडियो सुनकर सारी जानकारियां पाती हैं। मेवात क्षेत्र जो अब नूंह जिले के नाम से जाना जाता है, यहां साक्षरता दर बहुत कम है। मुस्लिम बहुल मेव समुदाय में साक्षरता दर की कमी के चलते यहां 14-15 साल की आयु में ही लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। लड़कियों को दूर-दराज के स्कूलों में पढ़ने भेजना तो यहां की संस्कृति के खिलाफ माना जाता था लेकिन कई एनजीओ और स्वयंसेवी संगठनों की पहल का नतीजा यह हुआ है कि अब यहां की लड़कियां न सिर्फ स्कूल-कॉलेजों में पढ़ने जाने लगी हैं बल्कि रोजगार पर प्रशिक्षण प्राप्त करके अपना व्यवसाय करने लगी हैं और जहां अवसर मिलता है घर-गांव से बाहर निकलकर रोज़गार भी प्राप्त कर रहीं हैं।

पिछले 5 सालों से रेडियो 'अल्फाज़ ए मेवात' न केवल समुदायकी महिलाओं से जुड़ा है बल्कि समाज के हर वर्ग बच्चों, किशोरों, किसानों, वृद्धों को विभिन्न रेडियो कार्यकमों के ज़रिये सूचना और जानकारी देकर आत्म-निर्भर बनाने में सहयोग कर रहा है ताकि वे अपने निर्णय खुद ले सकें और समाज में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। रेडियो द्वारा मुख्य कार्यक्रम जो लोगों की जिन्दगी का हिस्सा बन गए हैं वे : किसान भाइयों के लिए कृषि खबर, तोहफा-ऐ-कुदरत-जल-जंगल- जमीन, महिलाओं को उनके स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी देने के लिए सेहत का पैगाम, मेवाती संस्कृति से रुबरु कराता है कार्यक्रम सूफी सफ़र, बच्चों को शिक्षा पर जानकारी देता है कार्यक्रम रेडियो स्कूल और वक़्त हमारा है. किशोरों के भावनात्मक स्वास्थ्य से जड़ी रेडियो श्रृंखला कुछ तुम कहो, कुछ हम कहें। आज यहां महिलाएं और किशोरियां इतनी सशक्त हुई हैं कि रेडियो कार्यक्रमों की लाइव चर्चोओं में भाग लेती हैं, अपनी राय प्रकट करती हैं, साथ ही गांव में कुछ महिला समूह ऐसे भी है जो रेडियो कार्यक्रमों को बनाने में भी सहयोग देते हैं।

बात शिक्षा की हो या चिकित्सा की, रोजगार की हो या घर-परिवार की, साफ-सफाई की हो या महिला स्वास्थ्य की, पेंशन की हो या कानून की, सूचना की हो या खाद्यान्न की यहां की महिलाएं घर बैठे सब जानकारी पा रही हैं। खास बात यह है कि रेडियो की लाइव चर्चाओं में सरकारी अधिकारी तथा अपने-अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ लोगों को पूरी जानकारी मुहैया कराते हैं। जैसे 'कानून की बात' कार्यक्रम की लाइव चर्चाओं में फोन करने वाले श्रोताओं को नूंह के मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी एवं विधिक सेवाएं के सचिव नरेंद्र सिंह रावत स्वयं फोन पर जानकारी देते थे। समाज कल्याण विभाग के अधिकारी पेंशन तथा अन्य सामाजिक योजनाओं पर लोगों के सवालों का निदान करते हैं। इसी प्रकार स्वास्थ्य एवं सफाई से जुड़ी जानकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी तथा डॉक्टर देते हैं, इसलिए लोगों की विश्वसनीयता एवं निर्भरता रेडियो पर बढ़ी है। नूंह जिले के लगभग 200 गांवों की कायाकल्प सामुदायिक रेडियो के प्रयासों से संभव होने लगा है और आज यहां महिलाओं की सोच में बदलाव आना शुरु हो गया है।

**(लेखिका सामुदायिक रेडियो से जुड़ी हैं)**

---

व्यंग्य

# ईवीएम के बहाने लोकतंत्र की रेकी!

राजेश सेन

*वोट डालते समय ईवीएम मशीन केवल 'पीं-पीं चीं-चीं' ही नहीं करती, बल्कि 'चें-चें पें-पें' करने वालों को दर-हक़ीक़त का आईना दिखाकर ठिकाने भी लगा देती है। चुनाव आयोग उस पर पक्का भरोसा करता है। और वह चुनाव-आयोग को ताकत प्रदान करती है। अब लोकतंत्र में जो लोग हारते हैं, उनके लिए तो अंगूर सदैव ही खट्टे बने रहेंगे। इसमें नई बात क्या है? और अगर अंगूर खट्टे न रहें, तो जीतने वालों की तरह ही हारने वाले भी मीठे अंगूरों की शिकंजी बनाकर मजे-मजे में ही डकार जाएं। तब किसी को किसी से कोई शिकायत ही नहीं रहे। मगर ऐसा होता नहीं है। चुनाव में किसी को जीतना तो किसी को हारना भी पड़ता है। और हारने वालों के लिए असंतोष का निष्पाप खंबा हमेशा नौचने-नुचाने के लिए सदैव हाजिर रहता है। उधर, देश का आम मतदाता अलग ही वजहों से परेशान है। उसके सामने ईवीएम विरोध के अपने मौलिक कारण हैं। उसकी शिकायत है कि ईवीएम पर हमारा वोट कब डल जाता है, स्साला... हमें कुछ पता ही नहीं चलता!*

ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठ खड़े हुए हैं। सवालियों को शक है कि ये मशीन केवल चुनाव के नतीजे ही नहीं उगल रही, बल्कि नतीजों के वास्तविक चुनाव को भी हजम कर रही है। उन्हें यह भी शुबहा है कि मशीन लोकतंत्र की अमानत में खयानत कर रही है। किसी के हिस्से के वोट किसी और को टिका रही है। अब मशीन तो मशीन है साहब! उसका अपना कोई विवेकशील मगज थोड़े ही ना होता है। उसे जैसी कमाण्ड दी जाएगी, वह वैसे ही तो नतीजे उगलेगी। जैसी पट्टी पढ़ाई जाएगी, वैसा ही तो ककहरा बांचेंगी। उसमें जिस रंगत का वोट डाला जाएगा, उसी रंगत का तो परिणाम बाहर आएगा। अब वह रामलाल का वोट शामलाल को तो फ़ोकट में गिफ्ट देने से रही।

वोट डालते समय ईवीएम मशीन केवल 'पीं-पीं चीं-चीं' ही नहीं करती, बल्कि 'चें-चें पें-पें' करने वालों को दर-हक़ीक़त का आईना दिखाकर ठिकाने भी लगा देती है। चुनाव आयोग उस पर पक्का भरोसा करता है। और वह चुनाव-आयोग को ताकत प्रदान करती है। अब लोकतंत्र में जो लोग हारते हैं, उनके लिए तो अंगूर सदैव ही खट्टे बने रहेंगे। इसमें नई बात क्या है? और अगर अंगूर खट्टे न रहें, तो जीतने वालों की तरह ही हारने वाले भी मीठे अंगूरों की शिकंजी बनाकर मजे-मजे में ही डकार जाएं। तब किसी को किसी से कोई शिकायत ही नहीं रहे। मगर ऐसा होता नहीं है। चुनाव में किसी को जीतना तो किसी को हारना भी पड़ता है। और हारने वालों के लिए असंतोष का निष्पाप खंबा हमेशा नौचने-नुचाने के लिए सदैव हाजिर रहता है।

उधर, देश का आम मतदाता अलग ही वजहों से परेशान है। उसके सामने ईवीएम विरोध के अपने मौलिक कारण हैं। उसकी शिकायत है कि ईवीएम पर हमारा वोट कब डल जाता है, स्साला... हमें कुछ पता ही नहीं चलता! वे मतदान के गोपनीय दड़बे में ईवीएम के सामने खड़े होकर जब वोट का बटन दबाते हैं, तो केवल एक हलकी से 'पींप' सुनकर चौंक जाते हैं। तब मतदान अधिकारी उन्हें बताता है कि 'अब बाहर आ जाइये जनाब! आपका वोट कभी का कास्ट हो चुका है!' अब बताओ भला, ये भी क्या लल्लू-लाल जैसा वोट डालना हुआ? जिस सत्ता बदल के लिए आम-जनता बहुतेरे दिनों से मन में अरमान संजोए बैठी थी, वह काम तो एक पल का पिद्दी-सा रैला निकला। पता ही नहीं चला और उनका वोट भी मशीन के पेट में गप्प-गुडुप्प हो गया। ये भी कोई मशीन है जो महीनों की इंतजारी को एक ही पल में जाया कर देती है! अरे भई वोट डलने-डालने का पहले कोई हो-हल्ला हो। वोट डले तो कुछ आग्रही-मनुहारी समय लगे। मतदाता को वोट डलने का कुछ मजे जैसी फील हो। तब माना जाए कि लोकतंत्र के खाते में वोट पड़ा है। अब ये मुई मशीन तो लोकतंत्र के लम्बे समय तक चलने वाले रेले-भाषण-वादे-कसमें-रोडशो-ढोल-धमाके आदि-आदि के हो-हल्ले का मजा ही बिगाड़ दे रही है। अब जब वोट डालने का मजा ही नहीं आये तो उसे डाले गए वोट का हम मतदाता क्या अचार डालें। कहने का मतलब यह कि ऐसे मतदाता ईवीएम मशीन की निष्पक्षता या अनिष्पक्षता को लेकर चिंतित नहीं हैं। और ना ही वे मशीन के मैनेज होने की संभावित संभावनाओं से दुःखी हैं। वे तो केवल मशीन की चुस्त-दुरुष्ट गतिशीलता को लेकर नाराज हैं।

उधर, सरजी ने भी ईवीएम की गड़बड़ी वाले ढ़लान पर अपने आदतन विरोध के खाली पैडल मारना शुरू कर दिए हैं। अब उनकों संतुष्ट करना तो चुनाव आयोग के दादा-परदादा के बूते में भी नहीं है। तब ये गरीब लोकतंत्र क्या खाकर उन्हें संतुष्ट करेगा। वे आज मशीन की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं। हो सकता है कल को वे लोकतंत्र और संविधान की व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठा देवें। सवाल उठाना उनका पालतू शौक है। और उनका सवाल हमेशा अछोर-छोर होता है। बल्कि एक सीमा पर जाकर उनका सवाल तो फिर भी अपनी निजी सीमाएं सरंडर करे दे। मगर सरजी की असंतुष्टि का कभी कोई छोर नहीं होता। वे अनंत हैं, और उनके विरोध की जिज्ञासाएं भी अनंत हैं! दरअसल, जहां जाकर लोकतंत्र की सीमाएं 'डेड-एंड' हो जाती हैं। वहां से तो सरजी का लोकतंत्र प्रारम्भ ही होता है। अब ऐसे में बेचारी ईवीएम मशीनें क्या खाकर उन्हें तृप्ति अता कर सकेंगी? अब भला आप ही बताइये?

**(लेखक स्वत्रंत व्यंग्यकार हैं)**

---

प्रेरक कहानी

# दशरथ-कौसल्या विवाह

एक बार नारद ऋषि लंका के राजा रावण से मिलने गए उस समय रावण ने गर्व से अपने सामर्थ्य का वर्णन किया। परंतु नारदजी ने उसे सावधान किया था कि सूर्यवंश के राजा दशरथ एवं रानी कौसल्या के पुत्र श्रीरामचंद्र के हाथों तुम्हारी मृत्यु है। इस भविष्यकी सत्यताकी जांच करनेके लिए रावण बह्मदेवसे मिला। ब्रह्मदेव ने कहा कि यह सत्य है तथा यह भी बताया कि आज से तीसरे दिन कोशल देश की राजधानी में राजा दशरथ का विवाह कौसल्या के साथ होनेवाला है। तब, यह विवाह ही न हो, इस हेतु रावण ने सेना भेजकर कौशल्या का अपहरण करवाया, परंतु स्त्री हत्या का पाप न लगे इस विचारसे उसे एक पेटी में बंदकर समुद्र में छोड दिया। उस पेटी को लेकर दो मछलियों में लडाई प्रारम्भ हो गई तथा उन्होंने आपस में निश्चित किया कि युद्ध में जिसकी विजय होगी वही उस पेटी का स्वामी होगा। उन्होंने वह पेटी एक द्वीप पर रखी। इधर अजपुत्र दशरथ को शल देश जाने के लिए परिजनों तथा सेना के साथ जलयान में बैठकर समुद्र मार्ग से निकले। यह ज्ञात होते ही रावण आकाश से शस्त्रवृष्टि करने लगा। उसने उस जलयान को तोडकर समुद्र में डुबा दिया। तब, दशरथ एक लकडी के सहारे तैर कर एक द्वीप पर पहुंचे। वहां उन्होंने एक पेटी देखी। पेटी खोलते ही भीतर कौसल्या दिखाई दी। दोनों ने एक-दूसरे को पूरी घटना बताई। संयोग से, दोनों का यह मिलन विवाह के दिन ही हुआ। अत्यंत आनंद से पंचमहाभूतों को साक्षी बनाकर दोनों ने विवाह किया। दोनों, दिन के समय उस द्वीप पर घूमते थे तथा रात्रि के समय पेटी में रहते थे। इस प्रकार उनका दिनचर्या चलती रही। उधर, युद्ध में विजयी मछली एक रात्रि उस पेटी के पास आई तथा उस पेटी को मुख से उठाकर लंका के किनारे रख दी। जब रावण गर्व के साथ ब्रह्मदेव की वाणी असत्य होनेकी सूचना देने ब्रह्मदेव के पास पहुंचा, तो उसे जानकारी मिली कि दशरथ तथा कौसल्या का विवाह हो चुका है तथा उनका पता भी ज्ञात हो गया। रावणने लौटकर वह पेटी मंगवाई तथा दोनों को मारने के लिए तलवार उठा ली। दशरथजी का क्षात्रवृत्ति जागृत हो गयी तथा वे युद्ध के लिए उद्यत हो गए, परंतु रावण की पत्नी साध्वी मंदोदरी ने रावण को समझाकर यह अनर्थ होने से रोक दिया। रावण को भी लगा कि मेरे इस कुकृत्य से राम तुरन्त अवतरित हो जाएंगे, इस भय से उसने दशरथ पर प्रहार करनेसे स्वयं को रोका एवं दशरथ-कौशल्या को विमान से अयोध्या भेज दिया। दोनों को सकुशल लौटा देखकर सभीको आनंद हुआ ।

---

Blogger

# आडवाणी होंगे भारत के अगले राष्ट्रपति

बाल मुकुन्द ओझा

पांच राज्यों के विधान सभा चुनाव के बाद भाजपा दोहरी खुशी से झूम रही है। चार राज्यों में सरकार बनाने के बाद उसकी निगाह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों की और है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह पहली बार होगा की भाजपा बिना विघ्न बाधा के अपनी पसंद का राष्ट्रपति पा रही है। इससे पूर्व भाजपा उपराष्ट्रपति अपनी पसंद का पा चुकी है। अब भाजपा बम बम है। भाजपा के पितृ पुरुष और सब से बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी भारत के अगले राष्ट्रपति होंगे इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। आडवाणी वर्तमान में भाजपा के कद्दावर नेता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें अपना गुरु मानते है। मोदी आडवाणी को राष्ट्रपति बनवाकर गुरु दक्षिणा देना चाहते है और यहीं सुनहरा मौका है।

यूपी में भाजपा की सरकार बनने से पार्टी को राज्यसभा में अपनी स्थिति मजबूत करने का मौका भी मिल गया है। इस चुनाव से पहले बीजेपी को अपने पसंद का राष्ट्रपति बनाने के लिये करीब 92 हजार वोटों की जरूरत थी अब यह जरूरत पूरी हो गयी है। यूपी, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनने से अगला राष्ट्रपति बीजेपी की पसंद का होगा। पांच राज्यों में चुनाव से पहले इलेक्ट्रोलर कॉलेज में एनडीए का वोट वैल्यू बहुमत से 75,076 कम था। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत मिलने के बाद यह आंकड़ा सिर्फ 20,000 रह जाएगा, जिसे आसानी से भरा जा सकता है। एनडीए बीजेडी, एआईएडीएमके सहित निर्दलीय सांसदों और विधायकों से मदद ले सकता है।

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल इस साल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल में निर्वाचित सांसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्य होते हैं। इसमें 4120 विधायक और 776 निर्वाचित सांसदों समेत 4896 मतदाता होते हैं। विधायकों के मत का मूल्य जिस राज्य का वे प्रतिनिधित्व करते हैं उसके आकार पर निर्भर करता है। लेकिन सांसद के मत का मूल्य समान रहता है और इसमें परिवर्तन नहीं होता है। निर्वाचक मंडल के कुल मतों का मूल्य 10 लाख 98 हजार 882 होता है। विधानसभा चुनाव से पहले राजग के पास 75 हजार 76 मतों की कमी थी। लेकिन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा मणिपुर में भाजपा के शानदार प्रदर्शन के बाद यह फासला घटकर 20 हजार मतों पर आ गया। अगर भाजपा अन्नाद्रमुक के 134 और बीजद के 117 विधायकों का समर्थन हासिल करने में कामयाब रही तो वह अपनी पसंद के व्यक्ति को आसानी से राष्टपति बना सकती है।

देश के 786 सांसद और 4120 विधायक समेत कुल 4896 निर्वाचित जन-प्रतिनिधि राष्ट्रपति चुनाव के मतदाता होते हैं। यही राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है। इसके हरेक मतदाता का मत-मूल्य निर्धारित होता है। हरेक राज्य के विधायक का मत-मूल्य उस राज्य की कुल आबादी के समान-अनुपात में होता है। इसीलिए इसे आनुपातिक प्रतिनिधित्व वाला निर्वाचक मंडल भी कहते हैं। इसमें देश भर के निर्वाचित विधायकों का जितना मत-मूल्य होता है, उतना ही सभी निर्वाचित सांसदों का भी होता है। फिलहाल, 2011 की मतगणना के मुताबिक, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल सामूहिक मत-मूल्य 10,98,882 है राष्ट्रपति चुनाव के लिए हरेक राज्य के विधायक के मत-मूल्य की गणना उसके सम्बन्धित राज्य की कुल जनसंख्या को वहां के निर्वाचित विधायकों की संख्या से विभाजित करके और इसके भागफल को भी 1000 से विभक्त करके किया जाता है। मसलन, यदि राजस्थान की आबादी 6,85,48,437 और उसके विधायकों की संख्या 200 है तो पहले 6,85,48,437 को 200 से विभाजित करेंगे। फिर भागफल 342742.185 को 1000 से विभक्त करेंगे। इस तरह राजस्थान के विधायक का मत-मूल्य 347 होगा। इस प्रक्रिया में बड़े और अधिक आबादी वाले राज्यों के विधायकों का मत-मूल्य छोटे और कम आबादी वाले राज्यों के विधायकों को मुकाबले काफी अधिक होता है। अभी देश के कुल 4120 निर्वाचित विधायकों का सकल मत-मूल्य 5,49,441 है। इतना ही सामूहिक मत-मूल्य लोकसभा के 543 और राज्यसभा के 243 निर्वाचित सांसदों का होता है। यानी एक सांसद का मत मूल्य 699 होगा।

अब देश के 12 राज्यों (गुजरात, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, असम, उत्तर प्रदेश गोवा मणिपुर और अरूणाचल प्रदेश) में बीजेपी की सरकारें हो गई हैं। जबकि 5 राज्यों (जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, नगालैंड और सिक्किम) में उसके सहयोगी दलों की सरकारें हैं। 11 मार्च की मोदी लहर के नतीजे आने के बाद अब ताजा स्थिति ये है कि देश के कुल 4120 विधायकों में से एनडीए के विधायकों की संख्या 1531 से बढ़कर 1777 हो गयी है। इसमें बीजेपी के विधायकों की संख्या 1101 से बढ़कर 1474 हो गयी है। जबकि एनडीए के सहयोगी दलों के विधायकों की संख्या 430 से घटकर 403 हो गयी है। उधर, लोकसभा की 543 सीटों में से बीजेपी के 281 सांसदों समेत एनडीए के कुल 339 सदस्य हैं। जबकि राज्यसभा की 243 सीटों में से बीजेपी के 56 सांसदों समेत एनडीए की कुल ताकत 78 सदस्यों की है। इस तरह देश के कुल 776 सांसदों में से एनडीए के खेमे में 413 सदस्य हैं। राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल में भाजपा नीत एनडीए का बहुमत आ जाने के बाद यह पूरी तरह स्पष्ट हो गया है की भारत का अगला राष्ट्रपति भाजपा का ही होगा। उपराष्ट्रपति भी इसी दल का होगा।

**(लेखक वरिष्ठ स्वतंत्र पत्रकार हैं)**